EXAM GENIUS

Presents

WEEKLY GENIUS BANKING AND FINANCE

In BILINGUAL

31 MAY - 6 JUNE 2026

India's No. 1 Platform for UPSC | SSC | BANK RAILWAY Exam

UPSC | SSC | BANK | RAILWAY | STATE EXAMS

Ques: According to the RBI Annual Report 2025-26, what is the share of ₹500 denomination notes in India's total currency in circulation from a value perspective?

प्रश्न: आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार, मूल्य के दृष्टिकोण से भारत में प्रचलन में कुल मुद्रा में ₹500 मूल्यवर्ग के नोटों की हिस्सेदारी कितनी है?

A) 41.2%
B) 16.1%
C) 50.5%
D) 86%
E) 98.45%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• According to the RBI Annual Report 2025-26, the volume of ₹500 denomination banknotes in circulation increased by about 11.2% during FY26.

• आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार, FY26 के दौरान प्रचलन में ₹500 मूल्यवर्ग के नोटों की संख्या में लगभग 11.2% की वृद्धि हुई।

• The number of ₹500 notes increased from 6,34,458 lakh pieces in FY25 to 7,05,482 lakh pieces by March 2026.

• मार्च 2026 तक ₹500 के नोटों की संख्या FY25 के 6,34,458 लाख पीस से बढ़कर 7,05,482 लाख पीस हो गई।

• In value terms, ₹500 notes in circulation rose from ₹31.72 lakh crore in FY25 to ₹35.27 lakh crore in FY26.

• मूल्य के आधार पर, ₹500 के नोटों का कुल मूल्य FY25 के ₹31.72 लाख करोड़ से बढ़कर FY26 में ₹35.27 लाख करोड़ हो गया।

• The number of detected counterfeit ₹500 notes increased by more than 20% during the financial year.

• इस वित्तीय वर्ष के दौरान पकड़े गए नकली ₹500 नोटों की संख्या में 20% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।

• In terms of volume, ₹500 notes accounted for the highest share of total banknotes at 41.2%.

• संख्या (वॉल्यूम) के आधार पर, कुल बैंक नोटों में ₹500 के नोटों की हिस्सेदारी सबसे

अधिक 41.2% रही।

• ₹10 denomination notes were the second most circulated notes with a share of 16.1%.

• ₹10 के नोट 16.1% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रहे।

• From a value perspective, ₹500 denomination notes constituted more than 86% of the total currency in circulation.

• मूल्य (वैल्यू) के दृष्टिकोण से, प्रचलन में कुल मुद्रा का 86% से अधिक हिस्सा ₹500 के नोटों का था।

• By 31 March 2026, 98.45% of the ₹2,000 notes that were in circulation at the time of the withdrawal announcement in May 2023 had been returned to the banking system.

• 31 मार्च 2026 तक, मई 2023 में वापसी की घोषणा के समय प्रचलन में मौजूद ₹2,000 के नोटों का 98.45% हिस्सा बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुका था।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• RBI Establishment – 1 April 1935
• भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना – 1 अप्रैल 1935
• Nationalised – 1 January 1949
• राष्ट्रीयकरण – 1 जनवरी 1949
• Headquarters – Mumbai, Maharashtra
• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
• First Governor – Sir Osborne Smith
• प्रथम गवर्नर – सर ऑसबोर्न स्मिथ
• First Indian Governor – C. D. Deshmukh
• प्रथम भारतीय गवर्नर – सी. डी. देशमुख
• Current RBI Governor – Sanjay Malhotra
• वर्तमान RBI गवर्नर – संजय मल्होत्रा

Ques: Under RBI's proposed framework, victims of small-value digital frauds may receive compensation up to how much amount?

प्रश्न: RBI के प्रस्तावित ढांचे के तहत छोटे डिजिटल धोखाधड़ी के पीड़ितों को अधिकतम कितनी राशि तक मुआवजा मिल सकता है?

A) ₹10,000
B) ₹15,000
C) ₹20,000
D) ₹25,000
E) ₹50,000

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) has outlined a regulatory agenda for FY 2026-27 focused on customer protection and strengthening the credit ecosystem.
• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ग्राहक संरक्षण और ऋण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने पर केंद्रित नियामक एजेंडा तैयार किया है।
• RBI plans to improve transparency, consistency in supervision, and risk management across regulated entities.
• आरबीआई विनियमित संस्थाओं में पारदर्शिता, निगरानी की एकरूपता और जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाने की योजना बना रहा है।
• A new framework has been proposed to compensate victims of small-value digital frauds up to ₹25,000.
• छोटे डिजिटल धोखाधड़ी मामलों के पीड़ितों को ₹25,000 तक मुआवजा देने के लिए एक नया ढांचा प्रस्तावित किया गया है।
• Customers may receive compensation even if they inadvertently shared their OTP, subject to prescribed conditions.
• निर्धारित शर्तों के अधीन ग्राहकों को मुआवजा तब भी मिल सकता है, यदि उन्होंने अनजाने में अपना OTP साझा कर दिया हो।
• RBI will strengthen KYC and Anti-Money Laundering (AML) supervision through a risk-based approach.
• आरबीआई जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से KYC और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) निगरानी को मजबूत करेगा।
• The Central Bank plans to expand the Digital Rupee (CBDC) pilot for Direct Benefit Transfer (DBT) and retail use cases.
• केंद्रीय बैंक डिजिटल रुपया (CBDC) पायलट का विस्तार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)

और खुदरा उपयोग के लिए करेगा।
• The Unified Lending Interface (ULI) and MuleHunter.ai platform will be expanded to improve fraud detection and digital lending services.
• धोखाधड़ी की पहचान और डिजिटल ऋण सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI) और MuleHunter.ai प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा।
• The overall objective is to build a safer, more transparent, and customer-centric financial ecosystem.
• इसका समग्र उद्देश्य अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और ग्राहक-केंद्रित वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Reserve Bank of India (RBI) Established – 1 April 1935
• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना – 1 अप्रैल 1935
• Headquarters – Mumbai, Maharashtra
• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
• Governor – Sanjay Malhotra
• गवर्नर – संजय मल्होत्रा
• Nationalised – 1 January 1949
• राष्ट्रीयकरण – 1 जनवरी 1949

Ques: In which year was the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) enacted in India?
प्रश्न: भारत में Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) किस वर्ष लागू किया गया था?

A) 2014
B) 2015
C) 2016
D) 2017
E) 2018

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) has completed 10 years of implementation in India.

• भारत में Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) के कार्यान्वयन के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं।

• The Code was enacted in 2016 to create a unified, creditor-driven, and time-bound insolvency resolution framework.

• यह संहिता वर्ष 2016 में एकीकृत, ऋणदाता-आधारित तथा समयबद्ध दिवाला समाधान ढांचा स्थापित करने के लिए लागू की गई थी।

• The IBC aims to resolve insolvency cases efficiently while maximizing the value of assets.

• IBC का उद्देश्य दिवाला मामलों का प्रभावी समाधान करते हुए परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करना है।

• Till March 2026, a total of 8,987 insolvency cases were admitted under the Code.

• मार्च 2026 तक इस संहिता के तहत कुल 8,987 दिवाला मामलों को स्वीकार किया गया।

• Out of these, 7,102 cases reached closure.

• इनमें से 7,102 मामलों का निपटारा किया गया।

• A total of 1,419 cases resulted in approved resolution plans.

• कुल 1,419 मामलों में समाधान योजनाओं को मंजूरी दी गई।

• Creditors realised more than ₹4 lakh crore through the resolution process.

• समाधान प्रक्रिया के माध्यम से ऋणदाताओं को ₹4 लाख करोड़ से अधिक की वसूली हुई।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• IBC Full Form – Insolvency and Bankruptcy Code

• IBC का पूर्ण रूप – दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता

• Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) was formed on 1 October 2016.

• भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) का गठन 1 अक्टूबर 2016 को हुआ था।
• IBBI works under the Ministry of Corporate Affairs.
• IBBI, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
• IBBI Headquarters – New Delhi
• IBBI मुख्यालय – नई दिल्ली
• IBBI Chairperson – Ravi Mital
• IBBI के अध्यक्ष – Ravi Mital
• Ministry of Corporate Affairs Headquarters – New Delhi
• कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय का मुख्यालय – नई दिल्ली

Ques: SEBI recently imposed a penalty of ₹28.6 crore on which company for alleged accounting fraud?
प्रश्न: सेबी ने हाल ही में कथित लेखा धोखाधड़ी (Accounting Fraud) के लिए किस कंपनी पर ₹28.6 करोड़ का जुर्माना लगाया है?

A) Tata Power / टाटा पावर

B) Adani Green Energy / अडानी ग्रीन एनर्जी

C) Suzlon Energy / सुजलॉन एनर्जी

D) NTPC Green Energy / एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी

E) JSW Energy / जेएसडब्ल्यू एनर्जी

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Securities and Exchange Board of India (SEBI) imposed a penalty of ₹28.6 crore on Suzlon Energy Ltd. (SEL) and its top executives.
• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड (SEL) और उसके शीर्ष अधिकारियों पर ₹28.6 करोड़ का जुर्माना लगाया।
• SEBI found that the company inflated its net worth through circular

transactions and misleading accounting entries.

• सेबी ने पाया कि कंपनी ने सर्कुलर लेन-देन और भ्रामक लेखांकन प्रविष्टियों के माध्यम से अपनी नेट वर्थ को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया।

• Suzlon sold its Operations and Maintenance Services (OMS) unit to its subsidiary for ₹2,000 crore in 2014.

• सुजलॉन ने वर्ष 2014 में अपनी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज (OMS) इकाई को अपनी सहायक कंपनी को ₹2,000 करोड़ में बेचा था।

• According to SEBI, false records were created that overstated the company's revenue and turnover.

• सेबी के अनुसार कंपनी के राजस्व और कारोबार को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने के लिए फर्जी रिकॉर्ड बनाए गए थे।

• The misreported accounts helped the company raise equity capital of about ₹1,800 crore and obtain loan restructuring benefits.

• गलत वित्तीय विवरणों के आधार पर कंपनी ने लगभग ₹1,800 करोड़ की इक्विटी पूंजी जुटाई और ऋण पुनर्गठन का लाभ प्राप्त किया।

• SEBI directed Suzlon and the concerned executives to pay the penalty within 45 days.

• सेबी ने सुजलॉन और संबंधित अधिकारियों को 45 दिनों के भीतर जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है।

• The regulator observed that the accounting irregularities had the potential to mislead investors and distort the true financial position of the company.

• नियामक ने माना कि इन लेखांकन अनियमितताओं से निवेशकों को गुमराह किया गया तथा कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति को विकृत रूप में प्रस्तुत किया गया।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• SEBI Established – 12 April 1988 (Statutory Status: 30 January 1992)

• सेबी की स्थापना – 12 अप्रैल 1988 (वैधानिक दर्जा: 30 जनवरी 1992)

• Headquarters – Mumbai, Maharashtra

• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र

• Chairman – Tuhin Kanta Pandey

• अध्यक्ष – तुहिन कांत पांडे

• SEBI Motto – Protecting the Interests of Investors in Securities

• उद्देश्य – प्रतिभूति निवेशकों के हितों का संरक्षण
• SEBI Act – 1992
• सेबी अधिनियम – 1992

Ques: RBI has planned to introduce polymer currency notes on a pilot basis in which denomination?
प्रश्न: RBI ने पायलट आधार पर किस मूल्यवर्ग के पॉलिमर मुद्रा नोट जारी करने की योजना बनाई है?

A) ₹20
B) ₹50
C) ₹10
D) ₹100
E) ₹500

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) will introduce ₹10 polymer currency notes on a field trial basis in five cities.
• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) पाँच शहरों में फील्ड ट्रायल के आधार पर ₹10 के पॉलिमर मुद्रा नोट जारी करेगा।
• The initial plan is to issue 100 crore pieces of ₹10 polymer notes.
• प्रारंभिक योजना के तहत ₹10 के 100 करोड़ पॉलिमर नोट जारी किए जाएंगे।
• The primary objective is to increase the lifespan of banknotes and reduce replacement costs.
• इसका मुख्य उद्देश्य मुद्रा नोटों की आयु बढ़ाना और प्रतिस्थापन लागत को कम करना है।
• Polymer notes are more durable and have a longer shelf life compared to traditional paper currency notes.
• पॉलिमर नोट पारंपरिक कागजी मुद्रा नोटों की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं और

उनकी उपयोग अवधि अधिक होती है।

• These notes also help in preventing counterfeiting because of their advanced security features.

• उन्नत सुरक्षा विशेषताओं के कारण ये नोट जालसाजी (Counterfeiting) को रोकने में भी सहायक होते हैं।

• Based on the success of the pilot project, RBI may consider introducing polymer notes in other denominations as well.

• पायलट परियोजना की सफलता के आधार पर RBI अन्य मूल्यवर्गों में भी पॉलिमर नोट जारी करने पर विचार कर सकता है।

• Australia was the first country in the world to introduce polymer banknotes for circulation.

• प्रचलन में पॉलिमर बैंकनोट शुरू करने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया था।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• RBI Established – 1 April 1935
• RBI की स्थापना – 1 अप्रैल 1935
• RBI Headquarters – Mumbai, Maharashtra
• RBI मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
• RBI Governor – Sanjay Malhotra
• RBI गवर्नर – संजय मल्होत्रा
• RBI Nationalisation – 1 January 1949
• RBI का राष्ट्रीयकरण – 1 जनवरी 1949

EXAM Genius

Ques: Under the Liberalised Remittance Scheme (LRS), what is the maximum amount an individual can remit abroad in a financial year?

प्रश्न: Liberalised Remittance Scheme (LRS) के तहत कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितनी राशि विदेश भेज सकता है?

A) USD 100,000
B) USD 150,000
C) USD 200,000
D) USD 250,000

E) USD 500,000

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• India’s outward remittances under the Liberalised Remittance Scheme (LRS) declined by 2% in FY26 due to global uncertainty and geopolitical tensions.

• वैश्विक अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनावों के कारण FY26 में Liberalised Remittance Scheme (LRS) के तहत भारत से होने वाले बाहरी प्रेषण (Outward Remittances) में 2% की गिरावट दर्ज की गई।

• According to data released by the Reserve Bank of India (RBI), total outward remittances fell to USD 28.9 billion in FY26 from USD 29.6 billion in FY25.

• Reserve Bank of India (RBI) के अनुसार कुल बाहरी प्रेषण FY25 के USD 29.6 बिलियन से घटकर FY26 में USD 28.9 बिलियन रह गया।

• The sharpest decline was seen in overseas education remittances, which fell by more than 20% to USD 2.3 billion.

• विदेशी शिक्षा के लिए भेजी जाने वाली राशि में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई, जो 20% से अधिक घटकर USD 2.3 बिलियन रह गई।

• Despite the overall decline, remittances for investment in equity and debt increased by 68% year-on-year to USD 440.22 million.

• कुल गिरावट के बावजूद इक्विटी और ऋण निवेश हेतु प्रेषण में 68% की वार्षिक वृद्धि हुई और यह USD 440.22 मिलियन तक पहुंच गया।

• Remittances for medical treatment abroad increased by 52% year-on-year to USD 3.91 million.

• विदेश में चिकित्सा उपचार के लिए भेजी जाने वाली राशि में 52% की वृद्धि हुई और यह USD 3.91 मिलियन हो गई।

• Under the LRS, resident individuals can remit up to USD 250,000 per financial year for permitted current and capital account transactions.

• LRS के तहत निवासी व्यक्ति अनुमत चालू और पूंजीगत लेन-देन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम USD 250,000 विदेश भेज सकते हैं।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Liberalised Remittance Scheme (LRS) was introduced by the Reserve Bank of India in 2004.

• Liberalised Remittance Scheme (LRS) को वर्ष 2004 में Reserve Bank of India द्वारा शुरू किया गया था।

• Maximum Remittance Limit – USD 250,000 per financial year

• अधिकतम प्रेषण सीमा – प्रति वित्तीय वर्ष USD 250,000

• Allowed Uses – Education, Travel, Investments, Property Purchase, Maintenance of Relatives, Medical Treatment, etc.

• अनुमत उपयोग – शिक्षा, यात्रा, निवेश, संपत्ति खरीद, रिश्तेदारों का भरण-पोषण, चिकित्सा उपचार आदि।

Ques: Under the recent Ministry of Corporate Affairs (MCA) notification, companies can invest up to what percentage of their annual CSR expenditure through Zero Coupon Zero Principal (ZCZP) instruments?
प्रश्न: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) की हालिया अधिसूचना के अनुसार, कंपनियाँ अपनी वार्षिक CSR व्यय का अधिकतम कितना प्रतिशत Zero Coupon Zero Principal (ZCZP) Instruments के माध्यम से निवेश कर सकती हैं?

A) 2%
B) 5%
C) 10%
D) 15%
E) 20%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has allowed companies to deploy a portion of their Corporate Social Responsibility (CSR) funds through Zero Coupon Zero Principal (ZCZP) instruments.

• Ministry of Corporate Affairs (MCA) ने कंपनियों को अपने Corporate Social Responsibility (CSR) फंड का एक हिस्सा Zero Coupon Zero Principal (ZCZP)

Instruments के माध्यम से निवेश करने की अनुमति दी है।

• Companies can now invest up to 10% of their annual CSR expenditure through ZCZP instruments.

• अब कंपनियाँ अपने वार्षिक CSR व्यय का अधिकतम 10% ZCZP Instruments के माध्यम से निवेश कर सकती हैं।

• ZCZP instruments are securities issued by Not-for-Profit Organisations (NPOs) listed on the Social Stock Exchange.

• ZCZP Instruments, Social Stock Exchange में सूचीबद्ध Not-for-Profit Organisations (NPOs) द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूतियाँ (Securities) हैं।

• These instruments do not pay interest (Zero Coupon) and do not repay the principal amount (Zero Principal).

• इन उपकरणों में न तो ब्याज दिया जाता है (Zero Coupon) और न ही मूलधन वापस किया जाता है (Zero Principal)।

• They function as a market-based philanthropic funding mechanism to support social development initiatives.

• ये सामाजिक विकास पहलों को समर्थन देने हेतु बाजार-आधारित परोपकारी वित्तपोषण (Philanthropic Funding) तंत्र के रूप में कार्य करते हैं।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Corporate Social Responsibility (CSR) provisions are governed under Section 135 of the Companies Act, 2013.

• Corporate Social Responsibility (CSR) के प्रावधान Companies Act, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत आते हैं।

• Eligible companies must spend at least 2% of their average net profits of the previous three financial years on CSR activities.

• पात्र कंपनियों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम-से-कम 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य है।

• CSR provisions apply if a company has:
Net worth of ₹500 crore or more
Turnover of ₹1,000 crore or more
Net profit of ₹5 crore or more

• CSR प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होते हैं जिनका:

शुद्ध मूल्य (Net Worth) ₹500 करोड़ या अधिक हो
टर्नओवर ₹1,000 करोड़ या अधिक हो
शुद्ध लाभ ₹5 करोड़ या अधिक हो

• Failure to comply with CSR provisions can attract penalties of up to ₹1 crore.
• CSR प्रावधानों का पालन न करने पर ₹1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
• The Social Stock Exchange operates under the regulatory framework of Securities and Exchange Board of India.
• Social Stock Exchange, Securities and Exchange Board of India के नियामक ढाँचे के अंतर्गत कार्य करता है।
• SEBI Headquarters – Mumbai
• SEBI मुख्यालय – Mumbai

Ques : According to the RBI, what was the year-on-year (YoY) growth rate of actual INR settlements for imports?
प्रश्न: RBI के अनुसार, आयात के लिए वास्तविक INR निपटान (Settlements) की वर्ष-दर-वर्ष (YoY) वृद्धि दर कितनी थी?

A) 2.7%
B) 6.5%
C) 9.5%
D) 25.0%
E) 41.2%

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) confirmed a steady rise in the use of the Indian Rupee (INR) for global trade invoicing and settlements.
• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वैश्विक व्यापार चालान (Invoicing) और निपटान (Settlements) में भारतीय रुपये (INR) के उपयोग में लगातार वृद्धि की पुष्टि की है।

• This internationalisation initiative helps businesses reduce exchange rate risks and lower transaction costs.

• रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की यह पहल व्यवसायों को विनिमय दर जोखिमों से बचाने और लेनदेन लागत कम करने में मदद करती है।

• Import invoicing in INR reached ₹2.85 lakh crore, registering a 9.5% year-on-year growth.

• रुपये में आयात चालान (Import Invoicing) ₹2.85 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो वर्ष-दर-वर्ष 9.5% की वृद्धि दर्शाता है।

• Export invoicing in INR increased to ₹3.27 lakh crore, reflecting a 6.5% year-on-year growth.

• रुपये में निर्यात चालान (Export Invoicing) बढ़कर ₹3.27 लाख करोड़ हो गया, जो वर्ष-दर-वर्ष 6.5% की वृद्धि को दर्शाता है।

• Actual INR settlements for imports recorded a sharp 41.2% year-on-year increase.

• आयात के लिए वास्तविक INR निपटान (Settlements) में वर्ष-दर-वर्ष 41.2% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

• Actual INR settlements for exports also increased by 2.7% during the period.

• इसी अवधि में निर्यात के लिए वास्तविक INR निपटान में 2.7% की वृद्धि दर्ज की गई।

• The growing use of INR in international trade supports India's efforts to strengthen the global acceptance of its currency.

• अंतरराष्ट्रीय व्यापार में INR का बढ़ता उपयोग भारतीय मुद्रा की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ाने के भारत के प्रयासों को मजबूत करता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• SRVA Full Form – Special Rupee Vostro Account

• SRVA का पूर्ण रूप – स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट

Ques: What is the maximum claim amount that can be handled by the Insurance Ombudsman under an insurance policy?

प्रश्न: बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) किसी बीमा पॉलिसी के अंतर्गत अधिकतम कितनी राशि तक के दावे की शिकायतों का निपटारा कर सकता है?

A) ₹10 lakh / ₹10 लाख

B) ₹25 lakh / ₹25 लाख

C) ₹50 lakh / ₹50 लाख

D) ₹75 lakh / ₹75 लाख

E) ₹1 crore / ₹1 करोड़

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Insurance Regulatory and Development Authority of India reported that the Insurance Ombudsman resolved 41,055 grievances during FY 2025–26.

• Insurance Regulatory and Development Authority of India के अनुसार, बीमा लोकपाल ने वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान 41,055 शिकायतों का निपटारा किया।

• Around 79% of the decisions were delivered in favour of policyholders, reflecting a strong consumer-centric dispute resolution mechanism.

• लगभग 79% निर्णय पॉलिसीधारकों के पक्ष में दिए गए, जो उपभोक्ता हितैषी विवाद निवारण प्रणाली को दर्शाता है।

• The Insurance Ombudsman system has established 18 centres across India.

• बीमा लोकपाल प्रणाली ने पूरे भारत में 18 केंद्र स्थापित किए हैं।

• The Insurance Ombudsman can entertain complaints where the claim amount does not exceed ₹50 lakh under an insurance policy.

• बीमा लोकपाल उन शिकायतों की सुनवाई कर सकता है जिनमें बीमा दावे की राशि ₹50 लाख से अधिक नहीं होती।

• Key focus areas include reducing complaints pending for more than 90 days, minimizing delays in complaint registration, and improving the handling of non-entertainable complaints.

• प्रमुख फोकस क्षेत्रों में 90 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों को कम करना, शिकायत पंजीकरण में देरी को घटाना तथा गैर-स्वीकार्य शिकायतों के निपटान में सुधार करना शामिल है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Insurance Regulatory and Development Authority of India is the apex regulatory body for the insurance sector in India.

• Insurance Regulatory and Development Authority of India भारत में बीमा क्षेत्र का सर्वोच्च नियामक निकाय है।

• IRDAI was established in 1999.

• IRDAI की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी।

• IRDAI Headquarters – Hyderabad

• IRDAI का मुख्यालय – Hyderabad

• Insurance Ombudsman was established to provide a cost-effective and speedy grievance redressal mechanism for policyholders.

• बीमा लोकपाल की स्थापना पॉलिसीधारकों को त्वरित एवं कम लागत वाली शिकायत निवारण सुविधा प्रदान करने के लिए की गई थी।

Ques: According to the RBI Annual Report released in May 2026, what was the total financial amount involved in bank fraud cases during FY 2025-26?
प्रश्न: मई 2026 में जारी आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक धोखाधड़ी के मामलों में शामिल कुल वित्तीय राशि कितनी थी?

A) ₹23,722 crore / ₹23,722 करोड़

B) ₹32,803 crore / ₹32,803 करोड़

C) ₹41,000 crore / ₹41,000 करोड़

D) ₹48,021 crore / ₹48,021 करोड़

E) ₹50,000 crore / ₹50,000 करोड़

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• According to the Reserve Bank of India's Annual Report released on 29 May 2026, banks and financial institutions reported a total of 10,114 fraud cases during FY 2025-26.

• 29 मई 2026 को जारी भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने कुल 10,114 धोखाधड़ी के मामलों की सूचना दी।

• Although the number of fraud cases declined sharply from 23,722 cases in FY 2024-25 to 10,114 cases in FY 2025-26, the total amount involved increased substantially.

• हालांकि धोखाधड़ी के मामलों की संख्या FY 2024-25 के 23,722 मामलों से घटकर FY 2025-26 में 10,114 रह गई, लेकिन इसमें शामिल कुल राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

• The total financial implication of these frauds rose to ₹48,021 crore in FY 2025-26 from ₹32,803 crore in FY 2024-25.

• इन धोखाधड़ियों से जुड़ी कुल वित्तीय राशि FY 2024-25 के ₹32,803 करोड़ से बढ़कर FY 2025-26 में ₹48,021 करोड़ हो गई।

• This trend indicates that while the frequency of fraud cases has reduced, the average size and severity of high-value frauds have increased significantly.

• यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि धोखाधड़ी के मामलों की संख्या तो घटी है, लेकिन बड़े मूल्य वाले घोटालों का औसत आकार और गंभीरता काफी बढ़ गई है।

• Compared with the previous year, the total amount involved in frauds increased by more than 46%, despite the decline in the number of reported cases.

• पिछले वर्ष की तुलना में रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या कम होने के बावजूद धोखाधड़ी में शामिल कुल राशि में 46% से अधिक की वृद्धि हुई है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• RBI Accounting Year – 1 April to 31 March
• आरबीआई लेखा वर्ष – 1 अप्रैल से 31 मार्च
• CFR Full Form – Central Fraud Registry
• CFR का पूर्ण रूप – सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री

Ques: What is the name of the unified online platform launched by the Ministry of Finance to help citizens trace unclaimed financial assets?
प्रश्न: नागरिकों को बिना दावा की गई वित्तीय परिसंपत्तियों (Unclaimed Financial

EXAM Genius

Assets) का पता लगाने में सहायता हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है?

A) Jan Dhan Portal / जन धन पोर्टल

B) Financial Asset Tracker / फाइनेंशियल एसेट ट्रैकर

C) Unclaimed Assets Portal / अनक्लेम्ड एसेट्स पोर्टल

D) Money Recovery Portal / मनी रिकवरी पोर्टल

E) Asset Search India / एसेट सर्च इंडिया

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Ministry of Finance launched a single unified online platform called the **Unclaimed Assets Portal**.

• वित्त मंत्रालय ने **Unclaimed Assets Portal** नामक एक एकीकृत ऑनलाइन मंच शुरू किया है।

• The portal was launched by M. Nagaraju, Secretary of the Department of Financial Services (DFS).

• इस पोर्टल का शुभारंभ वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव M. Nagaraju द्वारा किया गया।

• Its primary objective is to help individuals locate and claim their forgotten or unclaimed financial assets.

• इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को उनकी भूली हुई या बिना दावा की गई वित्तीय परिसंपत्तियों का पता लगाने और उन्हें प्राप्त करने में सहायता करना है।

• The portal provides a single-window platform for searching unclaimed assets across the financial ecosystem.

• यह पोर्टल पूरे वित्तीय तंत्र में बिना दावा की गई परिसंपत्तियों की खोज हेतु एक सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

• The platform was developed in collaboration with the PSB Alliance.

• यह मंच PSB Alliance के सहयोग से विकसित किया गया है।

• The initiative builds upon the nationwide campaign "Your Money, Your Right".

• यह पहल देशव्यापी अभियान “Your Money, Your Right” पर आधारित है।

Citizens can search for:

- Unclaimed Bank Deposits
- Unclaimed Insurance Claims
- Unclaimed Shares
- Unclaimed Dividends
- Unclaimed Mutual Funds

नागरिक निम्नलिखित की खोज कर सकते हैं:

- बिना दावा की गई बैंक जमा राशि
- बिना दावा किए गए बीमा दावे
- बिना दावा किए गए शेयर
- बिना दावा किए गए लाभांश (Dividend)
- बिना दावा किए गए म्यूचुअल फंड निवेश

Ques: According to the RBI analysis, what was the average growth rate of outstanding bank time deposits between 2020-21 and 2024-25?

प्रश्न: आरबीआई विश्लेषण के अनुसार, 2020-21 और 2024-25 के बीच बकाया बैंक सावधि जमा (Time Deposits) की औसत वृद्धि दर क्या थी?

A) 5.3%
B) 10.7%
C) 15.5%
D) 32.4%
E) 42.1%

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• According to an RBI analysis, bank time deposits and debt mutual funds function as complementary investment avenues in both surplus and deficit liquidity conditions.

• आरबीआई के विश्लेषण के अनुसार, बैंक सावधि जमा (Time Deposits) और डेट म्यूचुअल फंड अधिशेष तथा घाटे दोनों प्रकार की तरलता स्थितियों में पूरक निवेश साधनों के रूप में कार्य करते हैं।

• Within India's bank-centric and evolving debt market, these two instruments mainly cater to different categories of investors, resulting in minimal direct competition.

• भारत के बैंक-केंद्रित और विकसित हो रहे ऋण बाजार में ये दोनों साधन मुख्य रूप से अलग-अलग निवेशक वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिससे इनके बीच सीधी प्रतिस्पर्धा कम होती है।

• The structural segmentation of investors encourages concurrent asset allocation rather than direct substitution between the two products.

• निवेशकों का यह संरचनात्मक विभाजन दोनों उत्पादों के बीच सीधे प्रतिस्थापन (Substitution) के बजाय सहवर्ती निवेश आवंटन (Concurrent Allocation) को बढ़ावा देता है।

• The RBI analysis found no statistically significant relationship between bank time deposits and equity mutual fund inflows.

• आरबीआई के विश्लेषण में बैंक सावधि जमा और इक्विटी म्यूचुअल फंड प्रवाह के बीच कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध नहीं पाया गया।

• Between 2020-21 and 2024-25, outstanding bank time deposits recorded an average annual growth of **10.7%**.

• वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच बकाया बैंक सावधि जमा में औसतन **10.7%** की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

• During the same period, Assets Under Management (AUM) of debt mutual funds increased by **5.3%**, while equity mutual funds expanded by **32.4%**.

• इसी अवधि में डेट म्यूचुअल फंड के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) में **5.3%** तथा इक्विटी म्यूचुअल फंड में **32.4%** की वृद्धि हुई।

Ques: In which state was the Credit Outreach Programme, where the Financial Inclusion 2.0 Vision Document was launched, organized?

प्रश्न: वह Credit Outreach Programme, जिसमें Financial Inclusion 2.0 Vision Document लॉन्च किया गया, किस राज्य में आयोजित किया गया था?

A) Assam / असम

B) Meghalaya / मेघालय

C) Tripura / त्रिपुरा

D) Manipur / मणिपुर

E) Mizoram / मिजोरम

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• A Credit Outreach Programme was organised at Udaipur in Gomati district of Tripura.

• एक Credit Outreach Programme का आयोजन Tripura के गोमती जिले के उदयपुर में किया गया।

• The programme was chaired by M. Nagaraju, Secretary of the Department of Financial Services (DFS), under the Ministry of Finance.

• इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव M. Nagaraju ने की।

• Various banks sanctioned loans worth ₹105.40 crore to 4,577 beneficiaries during the programme.

• कार्यक्रम के दौरान विभिन्न बैंकों ने 4,577 लाभार्थियों को ₹105.40 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए।

• National Bank for Agriculture and Rural Development and Small Industries Development Bank of India announced sanctions of more than ₹2 crore for various development projects.

• National Bank for Agriculture and Rural Development और Small Industries Development Bank of India ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए ₹2 करोड़ से अधिक की स्वीकृतियों की घोषणा की।

• A Cluster Development Branch of SIDBI was inaugurated at Udaipur to strengthen the MSME sector.

• MSME क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए उदयपुर में SIDBI की एक Cluster Development Branch का उद्घाटन किया गया।
• During the event, the Department of Financial Services launched the Financial Inclusion 2.0 Vision Document.
• इस कार्यक्रम के दौरान वित्तीय सेवा विभाग ने Financial Inclusion 2.0 Vision Document लॉन्च किया।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Department of Financial Services (DFS) functions under the Ministry of Finance.
• वित्तीय सेवा विभाग (DFS) वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
• Small Industries Development Bank of India was established on 2 April 1990.
• Small Industries Development Bank of India की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी।
• SIDBI Headquarters – Lucknow
• SIDBI मुख्यालय – Lucknow
• National Bank for Agriculture and Rural Development was established in 1982.
• National Bank for Agriculture and Rural Development की स्थापना 1982 में हुई थी।
• NABARD Headquarters – Mumbai
• NABARD मुख्यालय – Mumbai
• Capital of Tripura – Agartala
• त्रिपुरा की राजधानी – Agartala

Ques : In which year was the Goods and Services Tax (GST) implemented in India?
प्रश्न: भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) किस वर्ष लागू किया गया था?

A) 2015
B) 2016
C) 2017

D) 2018
E) 2019

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• India's gross GST collection crossed ₹1.94 lakh crore in May.
• भारत का सकल GST संग्रह मई माह में ₹1.94 लाख करोड़ से अधिक रहा।
• The strong GST revenue reflects sustained economic activity and improved tax compliance across the country.
• मजबूत GST राजस्व देश में निरंतर आर्थिक गतिविधियों और बेहतर कर अनुपालन को दर्शाता है।
• GST collections are an important indicator of consumption, trade, and business performance in the economy.
• GST संग्रह अर्थव्यवस्था में उपभोग, व्यापार और व्यावसायिक प्रदर्शन का महत्वपूर्ण संकेतक है।
• Higher GST revenue strengthens the government's fiscal position and enhances its capacity for public expenditure.
• GST राजस्व में वृद्धि सरकार की वित्तीय स्थिति को मजबूत करती है तथा सार्वजनिक व्यय क्षमता को बढ़ाती है।
• Increased collections also indicate better digitization and greater efficiency in tax administration.
• उच्च संग्रह कर प्रशासन में बेहतर डिजिटलीकरण और अधिक दक्षता को भी दर्शाता है।
• GST has simplified India's indirect tax structure by integrating multiple taxes into a single tax system.
• GST ने विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत कर भारत की कर व्यवस्था को सरल बनाया है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• GST Full Form – Goods and Services Tax
• GST का पूर्ण रूप – वस्तु एवं सेवा कर
• GST Implemented in India – 1 July 2017

• भारत में GST लागू – 1 जुलाई 2017
• Constitutional Amendment – 101st Constitutional Amendment Act, 2016
• संवैधानिक संशोधन – 101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016
• GST Council Chairman – Nirmala Sitharaman
• GST परिषद की अध्यक्ष – निर्मला सीतारमण
• GST Council Established – 2016
• GST परिषद की स्थापना – 2016
• GST Council Headquarters – New Delhi
• GST परिषद का मुख्यालय – नई दिल्ली
• Recent Gross GST Collection (May) – More than ₹1.94 Lakh Crore
• हालिया सकल GST संग्रह (मई) – ₹1.94 लाख करोड़ से अधिक

Ques: IRDAI imposed a penalty of ₹1 crore on which company for violations related to motor insurance guidelines?
प्रश्न: IRDAI ने मोटर बीमा दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए ₹1 करोड़ का जुर्माना किस कंपनी पर लगाया?

A) Bajaj Finance Ltd. / बजाज फाइनेंस लिमिटेड

B) Tata Motors Finance Ltd. / टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड

C) Nissan Renault Financial Services India / निसान रेनॉल्ट फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया

D) Mahindra Finance Ltd. / महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड

E) HDFC Ergo General Insurance / एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) imposed a penalty of ₹1 crore on Nissan Renault Financial Services India.
• भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने Nissan Renault

Financial Services India पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया।
• The penalty was imposed for violations related to motor insurance service guidelines and other regulatory norms.
• यह जुर्माना मोटर बीमा सेवा दिशानिर्देशों एवं अन्य नियामकीय प्रावधानों के उल्लंघन के कारण लगाया गया।
• Nissan Renault Financial Services India operates as a corporate agent in the insurance sector.
• Nissan Renault Financial Services India बीमा क्षेत्र में एक कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य करती है।
• IRDAI directed the company to place the order before its Board in the upcoming board meeting.
• IRDAI ने कंपनी को आगामी बोर्ड बैठक में इस आदेश को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
• The company has been asked to submit a copy of the board discussion minutes to the regulator.
• कंपनी को बोर्ड चर्चा की कार्यवाही (Minutes) की एक प्रति नियामक को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।
• IRDAI also instructed the company to submit an Action Taken Report (ATR) within 90 days from the date of the order.
• IRDAI ने कंपनी को आदेश की तिथि से 90 दिनों के भीतर Action Taken Report (ATR) जमा करने का निर्देश भी दिया।
• The action reflects IRDAI's strong commitment towards ensuring regulatory compliance and protecting policyholders' interests.
• यह कार्रवाई बीमा क्षेत्र में नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करने और पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के प्रति IRDAI की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
• Such regulatory measures help maintain transparency, accountability, and consumer confidence in the insurance sector.
• इस प्रकार की नियामकीय कार्रवाई बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता विश्वास को बनाए रखने में सहायक होती है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India)
• Established – 1999

• स्थापना – 1999
• Headquarters – Hyderabad, Telangana
• मुख्यालय – हैदराबाद, तेलंगाना
• Chairperson – Ajay Seth
• अध्यक्ष – अजय सेठ
• IRDAI Act Enacted – 1999
• IRDAI अधिनियम – 1999

Ques: Which Japanese financial institution entered into a strategic partnership with HDFC Capital Advisors Limited to invest in affordable and mid-income housing projects in India?
प्रश्न: भारत में किफायती एवं मध्यम आय वर्ग के आवासीय परियोजनाओं में निवेश हेतु HDFC Capital Advisors Limited के साथ रणनीतिक साझेदारी किस जापानी वित्तीय संस्थान ने की है?

A) Development Bank of Japan (DBJ) / डेवलपमेंट बैंक ऑफ जापान

B) Japan Bank for International Cooperation (JBIC) / जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन

C) Japan International Cooperation Agency (JICA) / जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी

D) Mitsubishi UFJ Financial Group / मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप

E) Sumitomo Mitsui Banking Corporation / सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• The Development Bank of Japan entered into a strategic partnership with HDFC Capital Advisors Limited to invest in real estate funds focused on affordable and mid-income housing projects in India.
• Development Bank of Japan ने भारत में किफायती एवं मध्यम आय वर्ग के

आवासीय परियोजनाओं में निवेश के लिए HDFC Capital Advisors Limited के साथ रणनीतिक साझेदारी की है।

• The partnership targets a total investment corpus of USD 1 billion.

• इस साझेदारी के तहत कुल USD 1 बिलियन के निवेश कोष (Corpus) का लक्ष्य रखा गया है।

• This is DBJ's first-ever real investment in India.

• यह भारत में DBJ का पहला प्रत्यक्ष (Real) निवेश है।

• DBJ has committed capital to the H-DREAM Fund (HDFC Capital Development of Real Estate Affordable and Mid-Income Fund), which is managed by HDFC Capital Advisors Limited.

• DBJ ने H-DREAM Fund (HDFC Capital Development of Real Estate Affordable and Mid-Income Fund) में पूंजी निवेश की प्रतिबद्धता जताई है, जिसका प्रबंधन HDFC Capital Advisors Limited द्वारा किया जाता है।

• The H-DREAM Fund has a target corpus of USD 500 million along with a USD 500 million greenshoe option.

• H-DREAM Fund का लक्ष्य कोष USD 500 मिलियन है, साथ ही USD 500 मिलियन का ग्रीनशू विकल्प भी उपलब्ध है।

• The fund has already secured commitments exceeding USD 350 million.

• इस फंड को अब तक USD 350 मिलियन से अधिक की निवेश प्रतिबद्धताएँ प्राप्त हो चुकी हैं।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Development Bank of Japan was established in 2008.

• Development Bank of Japan की स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी।

• DBJ Headquarters – Tokyo

• DBJ का मुख्यालय – Tokyo

• Chairman of DBJ – Mitsuru Ota

• DBJ के अध्यक्ष – Mitsuru Ota

• President of DBJ – Seiji Jige

• DBJ के अध्यक्ष (President) – Seiji Jige

• Japan Capital – Tokyo

• जापान की राजधानी – Tokyo

Ques: In May 2026, UPI recorded transactions worth how much?
प्रश्न: मई 2026 में यूपीआई के माध्यम से कुल कितने मूल्य के लेनदेन दर्ज किए गए?

A) ₹25.90 lakh crore / ₹25.90 लाख करोड़

B) ₹27.50 lakh crore / ₹27.50 लाख करोड़

C) ₹29.90 lakh crore / ₹29.90 लाख करोड़

D) ₹31.20 lakh crore / ₹31.20 लाख करोड़

E) ₹33.00 lakh crore / ₹33.00 लाख करोड़

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• India's Unified Payments Interface (UPI) processed a record 23.20 billion transactions in May 2026.

• भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने मई 2026 में रिकॉर्ड 23.20 बिलियन लेनदेन संसाधित किए।

• The total transaction value reached an all-time high of ₹29.90 lakh crore.

• कुल लेनदेन मूल्य ₹29.90 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।

• Transaction volume increased by 4% month-on-month from 22.35 billion in April 2026.

• लेनदेन संख्या अप्रैल 2026 के 22.35 बिलियन से बढ़कर 4% मासिक वृद्धि के साथ 23.20 बिलियन हो गई।

• Transaction value rose by 3% month-on-month from ₹29.03 lakh crore in April 2026.

• लेनदेन मूल्य अप्रैल 2026 के ₹29.03 लाख करोड़ से बढ़कर 3% मासिक वृद्धि के साथ ₹29.90 लाख करोड़ हो गया।

• Average daily transaction volume reached 748 million transactions.

• औसत दैनिक लेनदेन संख्या 748 मिलियन तक पहुंच गई।

• The average daily transaction value stood at ₹96,465 crore.

• औसत दैनिक लेनदेन मूल्य ₹96,465 करोड़ रहा।

• PhonePe and Google Pay continued to dominate the UPI ecosystem with

more than 80% market share.

• फोनपे और गूगल पे ने 80% से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ यूपीआई इकोसिस्टम में अपना दबदबा बनाए रखा।

• Growth in UPI transactions was driven by IPL-related spending, summer travel, and seasonal consumption trends.

• यूपीआई लेनदेन में वृद्धि आईपीएल से जुड़े खर्च, ग्रीष्मकालीन यात्रा और मौसमी उपभोग प्रवृत्तियों के कारण हुई।

• UPI is currently operational in seven countries, including the UAE, Singapore, Bhutan, Nepal, and Mauritius.

• यूपीआई वर्तमान में यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल और मॉरीशस सहित सात देशों में संचालित है।

• The achievement reflects India's rapidly expanding digital payment ecosystem and increasing adoption of cashless transactions.

• यह उपलब्धि भारत के तेजी से विस्तारित हो रहे डिजिटल भुगतान तंत्र और नकदी रहित लेनदेन की बढ़ती स्वीकृति को दर्शाती है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

NPCI (National Payments Corporation of India)

• Establishment – 2008

• स्थापना – 2008

• Headquarters – Mumbai, Maharashtra

• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र

• MD & CEO – Dilip Asbe

• एमडी एवं सीईओ – दिलीप अस्बे

UPI (Unified Payments Interface)

• Launched – April 2016

• शुभारंभ – अप्रैल 2016

• Developed By – NPCI

• विकसित किया गया – NPCI

Ques: According to RBI's proposed wallet regulations, what is the proposed monthly limit for person-to-person (P2P) wallet transfers?
प्रश्न: RBI के प्रस्तावित वॉलेट नियमों के अनुसार व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) वॉलेट ट्रांसफर की मासिक सीमा कितनी प्रस्तावित की गई है?

A) ₹10,000 / ₹10,000
B) ₹20,000 / ₹20,000
C) ₹25,000 / ₹25,000
D) ₹50,000 / ₹50,000
E) ₹1,00,000 / ₹1,00,000

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) has proposed stricter regulations for mobile wallets and prepaid payment instruments (PPIs).
• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मोबाइल वॉलेट और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPIs) के लिए कड़े नियम प्रस्तावित किए हैं।
• Under the proposed framework, person-to-person (P2P) wallet transfers may be capped at ₹25,000 per month.
• प्रस्तावित ढांचे के तहत व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) वॉलेट ट्रांसफर की सीमा ₹25,000 प्रति माह निर्धारित की जा सकती है।
• RBI has proposed mandatory Full-KYC for wallet users, reducing the role of minimum-KYC wallets.
• RBI ने वॉलेट उपयोगकर्ताओं के लिए Full-KYC को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे न्यूनतम-KYC वॉलेट की भूमिका सीमित हो जाएगी।
• Monthly cash loading limits in wallets are proposed to be reduced from ₹50,000 to ₹10,000.
• वॉलेट में नकद लोडिंग की मासिक सीमा ₹50,000 से घटाकर ₹10,000 करने का प्रस्ताव है।
• Minimum-KYC wallets may be restricted only to payments for goods and services.
• न्यूनतम-KYC वॉलेट को केवल वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान तक सीमित किया जा

सकता है।

• Full-KYC wallets will be required to integrate with UPI and card networks to ensure interoperability.

• Full-KYC वॉलेट को इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए UPI और कार्ड नेटवर्क से जोड़ना अनिवार्य होगा।

• The proposed rules aim to create a clearer distinction between wallet services and traditional banking products.

• प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य वॉलेट सेवाओं और पारंपरिक बैंकिंग उत्पादों के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित करना है।

• Fintech companies have raised concerns that these changes could affect wallet adoption and high-volume transaction use cases.

• फिनटेक कंपनियों ने चिंता व्यक्त की है कि ये बदलाव वॉलेट अपनाने की दर और उच्च-लेनदेन उपयोग मामलों को प्रभावित कर सकते हैं।

• The framework seeks to strengthen regulatory oversight, improve customer protection, and enhance transparency in digital payments.

• यह ढांचा नियामकीय निगरानी को मजबूत करने, उपभोक्ता सुरक्षा बढ़ाने और डिजिटल भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता लाने का प्रयास करता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

Reserve Bank of India (RBI)

• Established – 1 April 1935
• स्थापना – 1 अप्रैल 1935
• Headquarters – Mumbai, Maharashtra
• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
• Governor – Sanjay Malhotra
• गवर्नर – संजय मल्होत्रा

Prepaid Payment Instruments (PPI)

• Regulated by – RBI
• विनियामक – RBI
• Used for – Digital wallets, prepaid cards and payment instruments
• उपयोग – डिजिटल वॉलेट, प्रीपेड कार्ड और भुगतान साधन
• Full Form of PPI – Prepaid Payment Instruments

• PPI का पूर्ण रूप – प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स

Ques: Bajaj Finserv Intelligence, launched in partnership with IIT Bombay, is primarily aimed at promoting which sector in India?
प्रश्न: IIT बॉम्बे के सहयोग से शुरू की गई "बजाज फिनसर्व इंटेलिजेंस" पहल का मुख्य उद्देश्य भारत में किस क्षेत्र को बढ़ावा देना है?

A) Renewable Energy / नवीकरणीय ऊर्जा

B) Space Technology / अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

C) Artificial Intelligence and Deep Technology / कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डीप टेक्नोलॉजी

D) Biotechnology / जैव प्रौद्योगिकी

E) Quantum Computing / क्वांटम कंप्यूटिंग

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Bajaj Finserv Limited (BFS), in partnership with the Indian Institute of Technology Bombay (IIT Bombay), announced the launch of "Bajaj Finserv Intelligence".
• बजाज फिनसर्व लिमिटेड (BFS) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (IIT बॉम्बे) के सहयोग से "बजाज फिनसर्व इंटेलिजेंस" पहल शुरू करने की घोषणा की।
• The initiative has been launched to strengthen India's research and innovation ecosystem in Artificial Intelligence (AI) and deep-technology.
• इस पहल का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डीप-टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत के अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।
• Through this programme, advanced research, innovation, and technology-driven entrepreneurship will be encouraged.
• इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्नत अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा।

• Bajaj Finserv group companies will invest between ₹1,500 crore and ₹2,000 crore over the next five years.

• बजाज फिनसर्व समूह की कंपनियाँ अगले पाँच वर्षों में ₹1,500 करोड़ से ₹2,000 करोड़ तक का निवेश करेंगी।

• The investment will focus on AI-driven startups and early-stage companies with strong scalability potential.

• यह निवेश AI आधारित स्टार्टअप्स और उच्च विकास क्षमता वाली शुरुआती चरण की कंपनियों पर केंद्रित होगा।

• The initiative aims to accelerate the development of indigenous technology solutions and strengthen India's position in emerging technologies.

• इस पहल का उद्देश्य स्वदेशी तकनीकी समाधानों के विकास को गति देना तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत की स्थिति को मजबूत करना है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

Bajaj Finserv Limited (BFS)

• Founded – 2007
• स्थापना – 2007
• Headquarters – Pune, Maharashtra
• मुख्यालय – पुणे, महाराष्ट्र
• Chairman and Managing Director – Sanjiv Bajaj
• अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – Sanjiv Bajaj

EXAM Genius

Ques: Which authority granted Indian Overseas Bank (IOB) the licence to establish a branch in GIFT City, Gujarat?

प्रश्न: इंडियन ओवरसीज़ बैंक (IOB) को GIFT City, गुजरात में शाखा स्थापित करने हेतु लाइसेंस किस प्राधिकरण ने प्रदान किया?

A) Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिज़र्व बैंक

B) Securities and Exchange Board of India (SEBI) / भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

C) International Financial Services Centres Authority (IFSCA) / अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

D) National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) / नाबार्ड

E) Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) / भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Indian Overseas Bank (IOB) has received a licence from the International Financial Services Centres Authority (IFSCA) to establish a branch in GIFT City, Gujarat.

• इंडियन ओवरसीज़ बैंक (IOB) को गुजरात के GIFT City में शाखा स्थापित करने के लिए International Financial Services Centres Authority (IFSCA) से लाइसेंस प्राप्त हुआ है।

• The licence was granted through an official communication dated June 1.

• यह लाइसेंस 1 जून की आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से प्रदान किया गया।

• The new branch will enable IOB to participate in global offshore banking operations.

• नई शाखा IOB को वैश्विक ऑफशोर बैंकिंग गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम बनाएगी।

• The branch will also facilitate foreign currency transactions and international financial services.

• यह शाखा विदेशी मुद्रा लेनदेन एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं को भी बढ़ावा देगी।

• The development aligns with IOB's strategy to expand its international banking footprint.

• यह कदम IOB की अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग उपस्थिति को मजबूत करने की रणनीति के अनुरूप है।

• The announcement comes shortly after the bank's board approved a plan to raise ₹5,000 crore in fresh capital.

• यह घोषणा बैंक के बोर्ड द्वारा ₹5,000 करोड़ की नई पूंजी जुटाने की योजना को मंजूरी देने के बाद की गई है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Indian Overseas Bank was established in 1937.
• इंडियन ओवरसीज़ बैंक (IOB) की स्थापना वर्ष 1937 में हुई थी।
• Headquarters – Chennai, Tamil Nadu
• मुख्यालय – चेन्नई, तमिलनाडु
• MD & CEO – Ajay Kumar Srivastava
• एमडी एवं सीईओ – अजय कुमार श्रीवास्तव
• International Financial Services Centres Authority was established in April 2020.
• IFSCA की स्थापना अप्रैल 2020 में की गई थी।
• IFSCA Headquarters – GIFT City, Gandhinagar, Gujarat
• IFSCA का मुख्यालय – GIFT City, गांधीनगर, गुजरात
• GIFT City stands for Gujarat International Finance Tec-City.
• GIFT City का पूर्ण रूप Gujarat International Finance Tec-City है।
• GIFT City is India's first International Financial Services Centre (IFSC).
• GIFT City भारत का पहला International Financial Services Centre (IFSC) है।

Ques: Who has been appointed as the Managing Director (MD) of Canara Bank by the Government of India?
प्रश्न: भारत सरकार द्वारा केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक (MD) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

A) K. Satyanarayana Raju / के. सत्यनारायण राजू

B) Brajesh Kumar Singh / ब्रजेश कुमार सिंह

C) Binod Kumar / बिनोद कुमार

D) Ashok Chandra / अशोक चंद्र

E) Debadatta Chand / देबदत्त चंद

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Government of India has appointed Brajesh Kumar Singh as the Managing Director (MD) of Canara Bank.
• भारत सरकार ने ब्रजेश कुमार सिंह को केनरा बैंक का प्रबंध निदेशक (MD) नियुक्त किया है।
• Prior to this appointment, he was serving as the Executive Director of Indian Bank.
• इस नियुक्ति से पहले वे इंडियन बैंक में कार्यकारी निदेशक (Executive Director) के रूप में कार्यरत थे।
• His tenure as Managing Director of Canara Bank will continue till 30 April 2029, the date of his superannuation.
• केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल 30 अप्रैल 2029 तक, अर्थात उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक रहेगा।
• Brajesh Kumar Singh has succeeded K. Satyanarayana Raju as the Managing Director of the bank.
• ब्रजेश कुमार सिंह ने बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में के. सत्यनारायण राजू का स्थान लिया है।
• The appointment is expected to strengthen the leadership and operational efficiency of Canara Bank.
• इस नियुक्ति से केनरा बैंक के नेतृत्व और परिचालन दक्षता को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
• Canara Bank is one of India's leading public sector banks with a wide banking network across the country.
• केनरा बैंक भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है, जिसका देशभर में व्यापक बैंकिंग नेटवर्क है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

Canara Bank

• Established – 1906
• स्थापना – 1906
• Founder – Ammembal Subba Rao Pai

• संस्थापक – Ammembal Subba Rao Pai
• Headquarters – Bengaluru, Karnataka
• मुख्यालय – बेंगलुरु, कर्नाटक
• Tagline – Together We Can
• टैगलाइन – Together We Can

Indian Bank

• Established – 1907
• स्थापना – 1907
• Headquarters – Chennai, Tamil Nadu
• मुख्यालय – चेन्नई, तमिलनाडु
• MD & CEO – Binod Kumar
• MD एवं CEO – Binod Kumar

Ques: Which inflation indicator will become India's primary producer inflation measure after the planned five-year transition period?
प्रश्न: प्रस्तावित पांच वर्षीय संक्रमण अवधि के बाद भारत का प्रमुख उत्पादक मुद्रास्फीति सूचकांक कौन-सा होगा?

A) Consumer Price Index (CPI) / उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

B) Wholesale Price Index (WPI) / थोक मूल्य सूचकांक

C) Producer Price Index (PPI) / उत्पादक मूल्य सूचकांक

D) GDP Deflator / जीडीपी डिफ्लेटर

E) Retail Inflation Index / खुदरा मुद्रास्फीति सूचकांक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• In a major reform of India's inflation measurement framework, the Government has decided to transition from the Wholesale Price Index (WPI) to

the Producer Price Index (PPI) over the next five years.

• भारत की मुद्रास्फीति मापन प्रणाली में एक बड़े सुधार के तहत सरकार ने अगले पांच वर्षों में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) से उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) की ओर संक्रमण करने का निर्णय लिया है।

• The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) will release the revised WPI series with base year 2022-23 on 15 June 2026, replacing the existing 2011-12 series.

• उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) 15 जून 2026 को 2022-23 आधार वर्ष वाली संशोधित WPI श्रृंखला जारी करेगा, जो वर्तमान 2011-12 आधार वर्ष श्रृंखला का स्थान लेगी।

• The revised WPI basket will expand from 697 commodities to 957 commodities.

• संशोधित WPI बास्केट में वस्तुओं की संख्या 697 से बढ़ाकर 957 कर दी जाएगी।

• New items such as solar energy, wind energy and nuclear electricity have been included in the revised basket.

• संशोधित बास्केट में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु विद्युत जैसी नई वस्तुओं को शामिल किया गया है।

• Along with the revised WPI, the Government will introduce Output PPI, Trial Input PPI and Service PPI.

• संशोधित WPI के साथ सरकार आउटपुट PPI, ट्रायल इनपुट PPI और सर्विस PPI भी शुरू करेगी।

• Service PPI will cover seven service sectors including banking, insurance, pension fund management, securities transactions, railways, air passenger transport and telecommunications.

• सर्विस PPI में बैंकिंग, बीमा, पेंशन फंड प्रबंधन, प्रतिभूति लेन-देन, रेलवे, हवाई यात्री परिवहन और दूरसंचार सहित सात सेवा क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा।

• According to DPIIT, both WPI and PPI will be published simultaneously during the five-year transition period.

• DPIIT के अनुसार पांच वर्षीय संक्रमण अवधि के दौरान WPI और PPI दोनों को एक साथ प्रकाशित किया जाएगा।

• After the transition period, WPI will be discontinued and PPI will become the primary producer inflation indicator of India.

• संक्रमण अवधि पूरी होने के बाद WPI को समाप्त कर दिया जाएगा और PPI भारत का प्रमुख उत्पादक मुद्रास्फीति सूचकांक बन जाएगा।

• Unlike WPI, which measures wholesale prices, PPI captures prices at the producer level (farm-gate/factory-gate) and includes both goods and services.
• WPI के विपरीत, जो थोक स्तर की कीमतों को मापता है, PPI उत्पादक स्तर (फार्म-गेट/फैक्ट्री-गेट) की कीमतों को मापता है तथा इसमें वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं।
• The Output PPI will initially cover 123 product categories comprising around 1,500 items.
• आउटपुट PPI के प्रारंभिक चरण में 123 उत्पाद श्रेणियां और लगभग 1,500 वस्तुएं शामिल होंगी।

Ques: India has recently launched cross-border UPI payment connectivity with which country?
प्रश्न: भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सीमा-पार UPI भुगतान कनेक्टिविटी शुरू की है?

A) Vietnam / वियतनाम

B) Thailand / थाईलैंड

C) Cambodia / कंबोडिया

D) Malaysia / मलेशिया

E) Laos / लाओस

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• India and Cambodia have launched cross-border payment connectivity between their digital payment systems.
• भारत और कंबोडिया ने अपने डिजिटल भुगतान प्रणालियों के बीच सीमा-पार भुगतान कनेक्टिविटी शुरू की है।
• Indian travellers can now make seamless payments in Cambodia using the Unified Payments Interface (UPI).

EXAM Genius

• भारतीय यात्री अब कंबोडिया में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से आसानी से भुगतान कर सकते हैं।
• NPCI International Payments Limited (NIPL) partnered with ACLEDA Bank Plc to enable the service.
• NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने यह सुविधा शुरू करने के लिए ACLEDA Bank Plc के साथ साझेदारी की है।
• The integration links India's UPI network with Cambodia's national KHQR payment system.
• यह एकीकरण भारत के UPI नेटवर्क को कंबोडिया की राष्ट्रीय KHQR भुगतान प्रणाली से जोड़ता है।
• Indian users can scan KHQR-enabled QR codes at merchant outlets across Cambodia and make payments directly through UPI apps.
• भारतीय उपयोगकर्ता कंबोडिया में KHQR-सक्षम QR कोड स्कैन करके सीधे UPI ऐप्स के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।
• The facility covers more than 4.5 million merchant locations across Cambodia.
• यह सुविधा कंबोडिया के 45 लाख से अधिक व्यापारी प्रतिष्ठानों तक उपलब्ध है।
• The initiative marks the first phase of collaboration between NIPL and ACLEDA Bank.
• यह पहल NIPL और ACLEDA Bank के बीच सहयोग के प्रथम चरण को दर्शाती है।
• The project has been implemented under the guidance of the Reserve Bank of India (RBI) and the National Bank of Cambodia.
• यह परियोजना भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल बैंक ऑफ कंबोडिया के मार्गदर्शन में लागू की गई है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

Unified Payments Interface (UPI)

• Launched – 2016
• शुरुआत – 2016
• Developed By – National Payments Corporation of India (NPCI)
• विकसितकर्ता – नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)
• Regulated By – Reserve Bank of India (RBI)

• विनियामक – भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)

NPCI International Payments Limited (NIPL)

• Established – 2020
• स्थापना – 2020
• Parent Organization – National Payments Corporation of India
• मूल संगठन – NPCI
• Headquarters – Mumbai, Maharashtra
• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र

Cambodia
• Capital – Phnom Penh
• राजधानी – नोम पेन्ह
• Currency – Cambodian Riel
• मुद्रा – कंबोडियन रियल
• National Bank – National Bank of Cambodia
• केंद्रीय बैंक – नेशनल बैंक ऑफ कंबोडिया

Ques: J&K Bank won the Gold Award at the Finacle Innovation Awards 2026 for which platform?
प्रश्न: जे&के बैंक ने फिनेकल इनोवेशन अवॉर्ड्स 2026 में किस प्लेटफॉर्म के लिए गोल्ड अवॉर्ड जीता?

A) Digital Payments Platform / डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म
B) Core Banking Platform / कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म
C) Data Insights & Analytics Platform / डेटा इनसाइट्स एवं एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म
D) Cyber Security Platform / साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म
E) Mobile Banking Platform / मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• J&K Bank won the Gold Award at the Finacle Innovation Awards 2026.
• जे&के बैंक ने फिनेकल इनोवेशन अवॉर्ड्स 2026 में गोल्ड अवॉर्ड जीता।
• The award was received in the category “Modern Technologies-led Innovation – Data Insights & Analytics Platform”.
• यह पुरस्कार “मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़-लेड इनोवेशन – डेटा इनसाइट्स एवं एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म” श्रेणी में मिला।
• The award ceremony was organized by Infosys Finacle in Mumbai.
• यह पुरस्कार समारोह मुंबई में Infosys Finacle द्वारा आयोजित किया गया था।
• J&K Bank MD & CEO Amitava Chatterjee and GM (Strategy & IT/CIO) Mohammad Muzaffar Wani received the award.
• जे&के बैंक के एमडी एवं सीईओ अमितावा चटर्जी तथा जीएम (स्ट्रेटेजी एवं आईटी/CIO) मोहम्मद मुज़फ्फर वानी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।
• The bank was recognized for its Data Insights & Analytics Platform, which uses AI and advanced analytics for better decision-making.
• बैंक को उसके डेटा इनसाइट्स एवं एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के लिए सम्मानित किया गया, जो AI और उन्नत विश्लेषण के माध्यम से बेहतर निर्णय लेने में सहायता करता है।
• Nearly 500 nominations from financial institutions were received for the awards, making the competition highly competitive.
• इस पुरस्कार के लिए वित्तीय संस्थानों से लगभग 500 नामांकन प्राप्त हुए, जिससे प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी रही।
• The platform supports customer analytics, forecasting, risk management, credit management, and operational efficiency through AI/ML applications.
• यह प्लेटफॉर्म AI/ML आधारित ग्राहक विश्लेषण, पूर्वानुमान, जोखिम प्रबंधन, क्रेडिट प्रबंधन तथा परिचालन दक्षता में सहायता करता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

J&K Bank
• Founded – 1938
• स्थापना – 1938
• Headquarters – Srinagar, Jammu & Kashmir
• मुख्यालय – श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर
• MD & CEO – Amitava Chatterjee
• एमडी एवं सीईओ – अमितावा चटर्जी

Infosys Finacle
• Banking Technology Platform of Infosys
• इन्फोसिस का बैंकिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म

• Organises Finacle Innovation Awards
• फिनेकल इनोवेशन अवॉर्ड्स का आयोजन करता है

Ques: Which Japanese financial group is establishing a $250 million fund dedicated to early and growth-stage Indian startups?
प्रश्न: प्रारंभिक एवं विकासशील चरण (Early and Growth-Stage) के भारतीय स्टार्टअप्स के लिए 250 मिलियन डॉलर का फंड स्थापित करने वाला जापानी वित्तीय समूह कौन-सा है?

A) Nomura Holdings / नोमुरा होल्डिंग्स
B) SoftBank Group / सॉफ्टबैंक ग्रुप
C) Sumitomo Mitsui Financial Group / सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप
D) Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) / मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप
E) Mizuho Financial Group / मिजुहो फाइनेंशियल ग्रुप

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• Japan's Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) is establishing a $250 million fund dedicated to early and growth-stage Indian startups.
• जापान का Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) प्रारंभिक एवं विकासशील चरण के भारतीय स्टार्टअप्स के लिए 250 मिलियन डॉलर का फंड स्थापित कर रहा है।
• The fund size is approximately ₹2,300–2,400 crore and may eventually expand to $400 million.
• इस फंड का आकार लगभग ₹2,300–2,400 करोड़ है और भविष्य में इसे बढ़ाकर 400 मिलियन डॉलर तक किया जा सकता है।
• The fund will primarily focus on the fintech sector.
• यह फंड मुख्य रूप से फिनटेक (Fintech) क्षेत्र पर केंद्रित रहेगा।
• MUFG aims to capitalize on the funding gap that has emerged as several traditional mega-investors have scaled back their investments.
• MUFG का उद्देश्य उन अवसरों का लाभ उठाना है जो पारंपरिक बड़े निवेशकों द्वारा निवेश कम किए जाने के कारण उत्पन्न फंडिंग गैप से पैदा हुए हैं।
• The fund will be led by Mayank Shiromani, who serves as Deputy Chief Investment Officer at MUFG Innovation Partners.

• इस फंड का नेतृत्व Mayank Shiromani करेंगे, जो MUFG Innovation Partners में डिप्टी चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं।
• The initiative highlights growing international interest in India's startup ecosystem, particularly in financial technology and innovation-driven businesses.
• यह पहल भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम, विशेषकर फिनटेक और नवाचार आधारित व्यवसायों में बढ़ती वैश्विक रुचि को दर्शाती है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) Established – 2005
• मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप (MUFG) की स्थापना – 2005
• Headquarters – Tokyo
• मुख्यालय – टोक्यो, जापान
• Country – Japan
• देश – जापान
• MUFG Full Form – Mitsubishi UFJ Financial Group
• MUFG का पूर्ण रूप – मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप
• Fintech Full Form – Financial Technology
• फिनटेक का पूर्ण रूप – फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी
• Japan Capital – Tokyo
• जापान की राजधानी – टोक्यो
• Currency of Japan – Japanese Yen (JPY)
• जापान की मुद्रा – जापानी येन (JPY)।

Ques: In the June 2026 Monetary Policy Review, the RBI kept the repo rate unchanged at what level?
प्रश्न: जून 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने रेपो रेट को किस स्तर पर अपरिवर्तित रखा?

A) 4.75%
B) 5.00%
C) 5.25%
D) 5.50%
E) 6.00%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Reserve Bank of India (RBI) Governor Sanjay Malhotra announced that the Monetary Policy Committee (MPC) has kept the repo rate unchanged at 5.25%.
• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने घोषणा की कि मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो रेट को 5.25% पर यथावत रखा है।
• The decision was taken to balance inflation risks and economic growth amid geopolitical tensions in West Asia and volatile crude oil prices.
• यह निर्णय पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच महंगाई जोखिम तथा आर्थिक विकास में संतुलन बनाए रखने के लिए लिया गया।
• All six MPC members unanimously voted to retain the "Neutral" policy stance.
• एमपीसी के सभी छह सदस्यों ने सर्वसम्मति से "तटस्थ (Neutral)" नीति रुख बनाए रखने के पक्ष में मतदान किया।
• RBI revised its FY27 GDP growth forecast downward from 6.9% to 6.6%.
• आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के जीडीपी वृद्धि अनुमान को 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है।
• The retail inflation forecast for FY27 was increased from 4.6% to 5.1%.
• FY27 के लिए खुदरा महंगाई (Retail Inflation) का अनुमान 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया गया है।
• Inflation concerns have increased due to supply-chain disruptions and rising crude oil prices linked to the West Asia conflict.
• पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं तथा बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों के कारण महंगाई संबंधी चिंताएँ बढ़ी हैं।
• The Standing Deposit Facility (SDF) rate remains at 5.00%.
• स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) दर 5.00% पर बनी हुई है।
• The Marginal Standing Facility (MSF) rate and Bank Rate continue at 5.50%.
• मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) दर और बैंक रेट 5.50% पर यथावत हैं।
• The next MPC meeting is scheduled from August 3 to 5, 2026.
• अगली एमपीसी बैठक 3 से 5 अगस्त 2026 तक आयोजित होगी।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

Reserve Bank of India (RBI)
• Established – 1935

• स्थापना – 1935
• Nationalised – 1949
• राष्ट्रीयकरण – 1949
• Headquarters – Mumbai, Maharashtra
• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
• Current Governor – Sanjay Malhotra
• वर्तमान गवर्नर – संजय मल्होत्रा
• First Governor – Sir Osborne Smith
• प्रथम गवर्नर – सर ऑसबोर्न स्मिथ
• First Indian Governor – C. D. Deshmukh
• प्रथम भारतीय गवर्नर – सी. डी. देशमुख
• RBI Emblem – Tiger and Palm Tree
• RBI का प्रतीक चिन्ह – बाघ और ताड़ का वृक्ष

RBI Policy Rates (June 2026)

• Repo Rate – 5.25%
• रेपो रेट – 5.25%
• SDF Rate – 5.00%
• एसडीएफ दर – 5.00%
• MSF Rate – 5.50%
• एमएसएफ दर – 5.50%
• Bank Rate – 5.50%
• बैंक रेट – 5.50%

Ques: The 'Niveshak Shivir' being organized in Bhopal by IEPFA and SEBI is primarily aimed at helping investors resolve issues related to what?
प्रश्न: IEPFA और SEBI द्वारा भोपाल में आयोजित 'निवेशक शिविर' का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को किससे संबंधित समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना है?

A) GST Refund Claims / जीएसटी रिफंड दावे
B) Income Tax Returns / आयकर रिटर्न
C) Unclaimed Dividends and Shares / दावा न किए गए लाभांश और शेयर
D) Bank Loan Settlements / बैंक ऋण निपटान
E) Insurance Premium Payments / बीमा प्रीमियम भुगतान

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA), under the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, and SEBI are organizing a day-long 'Niveshak Shivir' in Bhopal.
• भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA) तथा SEBI द्वारा भोपाल में एक दिवसीय 'निवेशक शिविर' आयोजित किया जा रहा है।
• The 'Niveshak Shivir' will function as a one-stop facilitation platform for investors.
• 'निवेशक शिविर' निवेशकों के लिए एक वन-स्टॉप सुविधा मंच के रूप में कार्य करेगा।
• The camp is designed to help investors resolve issues related to unclaimed dividends and shares.
• यह शिविर निवेशकों को दावा न किए गए लाभांश (Unclaimed Dividends) और शेयरों से संबंधित समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करेगा।
• Investors will also be able to access various investor services directly through the platform.
• इस मंच के माध्यम से निवेशकों को विभिन्न निवेशक सेवाओं तक प्रत्यक्ष पहुंच भी प्राप्त होगी।
• The initiative will provide on-ground grievance redressal mechanisms for investor complaints and concerns.
• यह पहल निवेशकों की शिकायतों और समस्याओं के लिए जमीनी स्तर पर शिकायत निवारण (Grievance Redressal) की सुविधा उपलब्ध कराएगी।
• The objective is to enhance investor awareness, protection and ease of access to financial services.
• इसका उद्देश्य निवेशक जागरूकता, संरक्षण और वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच को बढ़ावा देना है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA) Established – 2016
• निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA) की स्थापना – 2016
• Parent Ministry – Ministry of Corporate Affairs
• संबद्ध मंत्रालय – कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
• SEBI Established – 12 April 1988 (Statutory Status: 30 January 1992)

- SEBI की स्थापना – 12 अप्रैल 1988 (वैधानिक दर्जा: 30 जनवरी 1992)
- Headquarters of SEBI – Mumbai
- SEBI का मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
- SEBI Chairman – Tuhin Kanta Pandey
- SEBI के अध्यक्ष – तुहिन कांत पांडे

EXAM Genius